

प्रेषक,

डा० हेमलता ढौडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 21 अप्रैल, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या 122/बजट/उ०खा०ग्रा०बो०/2008-09 दिनांक 16 अप्रैल, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन निर्माण योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु टी०ए०सी० (वित्त) द्वारा संस्तुत धनराशि रुपये 465.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या 1126/VII-2/03-खादी/2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 द्वारा रु० 65.80 लाख, शासनादेश संख्या 275/VII-2/07/03-खादी/2006 दिनांक 13 फरवरी, 2007 द्वारा रु० 60.00 लाख, शासनादेश संख्या: 2742/VII-2/03-खादी/2006 दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा रु० 33.33 लाख, शासनादेश संख्या: 4670/VII-2/03-खादी/2006 दिनांक 13 सितम्बर, 2007 द्वारा रु० 76.67 लाख एवं शासनादेश संख्या: 1420/VII-2/03-खादी/2006 दिनांक 27 मार्च 2008 द्वारा रु० 20.38 लाख अर्थात् आपके निर्वर्तन पर रखी गयी कुल रु० 256.18 लाख की धनराशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु अंतिम किस्त के रूप में अवशेष रु० 208.82 लाख (रु० दो करोड़ आठ लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निर्वर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का एकमुस्त आहरण कर खादी बोर्ड के माध्यम से निर्माण एजेन्सी को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता हो यह करते समय

वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपयोग भवन निर्माण/आवास संबंधित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 1126/VII-2/03-खादी/2006 दिनांक 27 मार्च, 2006 में इंगित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4- वर्षान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण 31 मार्च 2009 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो दिनांक: 31.03.2009 तक शासन को समर्पित किया जायेगा। व्यय उन्हीं योजना/कार्यों पर किया जाय जिन कार्यों हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखाशीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 00-आयोजनागत, 102-लघु उद्योग, 06-उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन निर्माण-00, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 के प्रस्तर-2 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फण्ड की पार्किंग न हो ताकि राज्य सरकार पर अनावश्यक रूप से ओवर ड्राफ्ट या अर्थोपाय अग्रिम पर व्याज की अधिक देनदारी न हो।

भवदीया,

(डा० हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1871(1)/VII-2/03-खादी/2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक निर्माण विंग उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-2
11. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(डा० हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।